International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, July-December 2024, Submitted in July 2024, ISSN -2393-8048

उदारीकरण के दौरान ग्रामीण आबादी की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन बिहार विशेष के संदर्भ में

Prabhat Kumar Singh, Research Scholar, Department of History, Purnea University, Purnia, Bihar (India)
Email: prabhatsingh.1470@gmail.com

यह पेपर समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद बिहार के धीमे आर्थिक विकास के बुनियादी कारणों की जांच करता है। पारंपरिक दृष्टिकोण के विपरीत, विश्लेषण से पता चलता है कि धीमी आर्थिक वृद्धि कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का परिणाम है जो संरचनात्मक, ऐतिहासिक और वृहद-आर्थिक नीतियों में अंतर्निहित हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान एक शोषक जमींदार वर्ग की स्थापना के कारण बिहार आर्थिक रूप से हाशिए पर था, जिसने 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी आर्थिक और सामाजिक प्रगति का विरोध करना जारी रखा। संघीय सरकार की "माल ढुलाई समानीकरण" की नीति, जिसने बिहार के प्राकृतिक संसाधन लाभ को एक से कम कर दिया, ने हाशिए पर जाने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और अन्य थोक संसाधनों जैसे औद्योगिक आदानों के लिए रेलवे माल ढुलाई के लिए सब्सिडी प्रदान करना। यह, बाद की योजना अवधि में केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधनों की अपेक्षाकृत कम मात्रा के संयोजन के साथ, इन राज्यों की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण मानव विकास की कमी हुई है। बिहार के खराब प्रदर्शन के लिए कम मानव पूंजी, कमजोर संस्थान और खराब बुनियादी ढांचे के साथ-साथ राजनीतिक अस्थिरता और जाति, वर्ग और जातीय विभाजन पर आधारित सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित सामाजिक संघर्ष को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

परिचय:

ओडिशा के बाद बिहार भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। समूची ग्रामीण गरीबी दर 62.3 प्रतिशत थी, जो पूरे भारत की 37.3 प्रतिशत दर से काफी अधिक थी। पिछले दस वर्षों में, राज्य ने सामाजिक-आर्थिक बदलाव देखे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। बिहार में पिछले दस वर्षों के दौरान देश के मुख्य राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या और घनत्व वृद्धि (1102/वर्ग किलोमीटर) हुई है। भारत के अधिकांश हिस्सों की तरह, राज्य को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ज्यादातर ग्रामीण, अविकसित अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। जब जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तो कई किसान सबसे स्पष्ट शोषक कृषि प्रणाली से मुक्त हो गए थे, लेकिन इसके परिणामस्वरूप किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ, और हालांकि भूमि संबंधों की संरचना में कुछ बदलाव आया, लेकिन प्रणाली अर्ध-सामंती बनी रही। 60.8% साक्षरता के साथ, यह देश का सबसे कम साक्षर राज्य है। भारत का बिहार राज्य घनी आबादी वाला और भ्रष्ट है। इसे अपने भ्रष्टाचार, अराजकता, बाढ़ और सूखे के कारण आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े राज्य के रूप में भी माना जाता है। महिलाओं की कम कार्य भागीदारी दर राज्य की कम कार्य भागीदारी दर का कारण है। विशेषज्ञ समूह के दृष्टिकोण के अनुसार, गरीबी की व्यापकता 1987 में 65.2 प्रतिशत से घटकर 1998-2021 में 57 प्रतिशत हो गई। गरीबी की अत्यधिक उच्च दर के अलावा, राज्य अधिकांश प्रमुख सामाजिक और मानव विकास मेट्रिक्स पर खराब प्रदर्शन करता है। मध्यम जातियों का उदय एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी जो 1985 के दशक में शुरू हुई और 1995 के दशक की शुरुआत में इसमें तेजी आई। मध्य जातियों ने समय के साथ प्रभाव प्राप्त किया। थोड़े खंडित होने के बावजूद, आर्थिक प्रगति के बिना यह राजनीतिक सशक्तिकरण अर्ध-सामंती संबंधों को समाप्त करने और ग्रामीण वातावरण को बदलने

में महत्वपूर्ण था। कानून और व्यवस्था में बड़े सुधार और विकास दर में बदलाव के कारण पिछले पांच से छह वर्षों के दौरान राज्य की छवि में सुधार हुआ है। वाणिज्य, भवन, परिवहन और संचार सहित उद्योगों की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि राज्य के बेहतर आर्थिक विकास के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। द्वितीयक और तृतीयक उद्योगों की अधिक विकास दर के परिणामस्वरूप राज्य के उत्पादन के क्षेत्रीय वितरण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। राज्य के 64% से अधिक कार्यबल को रोजगार देने के बावजूद, कृषि राज्य के सकल राज्य उत्पाद का केवल 8% है। पिछले तीस वर्षों या उससे अधिक समय में बिहार ने जबरदस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं। भले ही विकास असमान रहा है, गरीबों ने कुछ सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण देखा है, विशेष रूप से मध्यम जाति के सदस्यों के बीच, और गरीबी में काफी कमी आई है, हालांकि आधी से अधिक आबादी अभी भी गरीबी में रहती है। हाल के विकास में तेजी, बढ़ी हुई शांति और व्यवस्था और संस्थानों और शासन को मजबूत करने के प्रयासों के

परिणामस्वरूप राज्य और अन्य हितधारकों में बहुत उम्मीद है।

यह कार्य महत्वपूर्ण विकास, अवसंरचनात्मक, संसाधन और संस्थागत अंतराल को दूर करना है ताकि इसे अधिक समावेशी और विविध बनाते हुए कम संख्या में लोगों द्वारा संचालित इस तेजी से विकास को बनाए रखा जा सके। ऐसा करने के लिए, राज्य, केंद्र और अन्य हितधारकों के पास एक स्पष्ट दृष्टि और एक सुविचारित योजना होनी चाहिए जो तथ्यात्मक आंकड़ों और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित हो। बिहार और उत्तर प्रदेश में विकास की ठहराव के मूल कारणों का पता लगाना उनकी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाने के लिए आवश्यक है। देश के आर्थिक विकास के विविध पैटर्न को क्रॉनिकल करने के बड़े पैमाने पर प्रयासों के बावजूद, भारत के अंदर अलग-अलग विकास पैटर्न के कारणों का विश्लेषण करने के लिए थोड़ा व्यवस्थित काम किया गया है (घोष, 2008; पार्कर और कोज़ेल, 2007) सूक्ष्म समस्याओं को अक्सर बड़े संरचनात्मक और नीतिगत चिंताओं की तुलना में अधिक ध्यान दिया गया है जो विकास पैटर्न को प्रभावित करते हैं (पार्कर और कोज़ेल, 2007; ठाकुर, बोस, हुसैन, और जनैया, 2000) यह अध्ययन व्यापक दृष्टिकोण से बिहार के निम्न सामाजिक-आर्थिक विकास के कारणों की जांच करता है। शोधपत्र का लक्ष्य यह समझना है कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को इंगित करने, उनके प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने या किसी भी विकास मॉडल की परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के बजाय, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न विचारधाराओं की जांच करके आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को किस शर्त पर रखा गया है। नतीजतन, इस पत्र का योगदान वर्णनात्मक है और इसका उद्देश्य बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति और प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का अधिक ज्ञान प्रदान करना है। बिहार की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ। गरीबी कम करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने पर विकास अर्थशास्त्र के प्राथमिक ध्यान के बावजूद, आर्थिक विकास में योगदान करने वाले कारकों के बारे में बहुत कम जानकारी है (केनी एंड विलियम्स, 2001) हालांकि अर्थमितीय विधियों में हाल की प्रगति ने एंडोजेनिटी और मॉडल अनिश्चितता की व्याख्या करना संभव बना दिया है (डॉलर, 1992; ब्रॉक एंड डर्लॉफ, 2001; डोपेलहोफर, मिलर, और साला-ए-मार्टिन, 2000; मिरस्टीन एंड त्सांगारिड्स, 2009) और अनुभवजन्य साहित्य ने क्रॉस-कंट्री विकास प्रदर्शन की हमारी समझ में सुधार

किया है, अर्थमितीय मॉडल सामाजिक दुनिया की जटिल कारण प्रकृति, अंतर्निहित आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में कम हो जाते हैं जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। चूँकि आर्थिक विकास एक बहुआयामी, जटिल और गतिशील प्रक्रिया है, इस तरह के विश्लेषण पर आधारित रणनीतियाँ और नीतियां अविकसितता के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रहती हैं (एडलमैन, 2001; केनी एंड विलियम्स, 2001) इस निबंध का मुख्य लक्ष्य उन कई तत्वों और अंतर्निहित तंत्रों को समझना है जो बिहार के अविकसित राज्य की ओर ले जाते हैं। यह वृहद नीतियों (राष्ट्रीय और राज्य दोनों) के साथ-साथ ऐतिहासिक और संरचनात्मक तत्वों को देखता है। भले ही बिहार अध्ययन का प्राथमिक फोकस है, लेकिन सीखा गया सबक अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि चीन, ब्राजील, मैक्सिको और नाइजीरिया सहित दुनिया भर के कई देशों को असमान विकास पैटर्न के साथ तुलनात्मक विकास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (जालान और रैवलियन, 2002; रैवलियन और चेन, 2007)I

इस अध्ययन में उपयोग की जाने वाली जानकारी विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्रोतों से आती है, जैसे किताबें, पत्रिकाएं, सरकारी कागजात और योजना आयोगों के रिकॉर्ड। कागज की संरचना इस प्रकार हैः आर्थिक विकास पर मौलिक साहित्य का विश्लेषण करके, दूसरा भाग राज्य के विकास प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को समझने के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार करता है। तीसरा खंड तब डेटा प्रस्तुत करता है और निष्कर्षों का स्पष्टीकरण प्रदान करता है। चौथा खंड बिहार के वर्तमान घटनाक्रमों पर चर्चा करता है और निष्कर्ष निकालता है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकः एक वैचारिक ढांचा आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत के बाद से, शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की है कि क्यों विभिन्न राष्ट्र-यहां तक कि एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न क्षेत्र-आर्थिक विकास की अलग-अलग दर प्राप्त करते हैं। 1701 के दशक में भौतिकविदों के लेखन को देखा गया जिन्होंने सोचा कि कृषि उत्पादन का एकमात्र स्रोत है और कृषि उत्पादकता के साथ एक देश की संपत्ति में वृद्धि हुई है (ब्रंसचवीलर, 2008; फोंटेन, 1996; स्टेनर, 2008) यह तब है जब राष्ट्रीय धन को प्रभावित करने वाले कारकों की खोज शुरू हुई। ओ 'ब्रायन (2005) के अनुसार एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और अन्य शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि पूंजी, श्रम और भूमि उत्पादन के प्राथमिक चालक और देश की संपत्ति के मुख्य स्रोत थे। गैलप, सैक्स और मेलिंगर (2000) डिंग एंड फील्ड (2006) और स्टिजन्स (2006) जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि और औद्योगिक विकास का मुख्य चालक संसाधन दान है, जिसमें प्राकृतिक धन, भूमि, मिट्टी, मौसम, जलवायु और खनिज संसाधन शामिल हैं। आर्थिक विकास दर और स्तर विभिन्न राष्ट्रों और क्षेत्रों के संसाधन दान के आधार पर भिन्न होते हैं (स्टिजन्स, 2006) यद्यपि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन निधि के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, शोधकर्ता इस बात पर असहमत हैं कि क्या यह एकमात्र निर्णायक कारक है। [2]. जाँच के अधीन गाँवों की विशेषताएं अध्ययन के अधीन गाँवों की विशेषताएं शोध में शामिल 37 गाँव बिहार के सात जिलों में फैले हुए हैं, जिनमें से चार उत्तर में (अरारिया, गोपालगंज, मधुबनी और पूर्णिया) और तीन दक्षिण में (गया, नालंदा और रोहतास) गंगा के हैं। मूल रूप से बिहार के मैदानी इलाकों की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए, गांवों के बीच, विशेष रूप से क्षेत्रों के बीच, लेकिन एक ही क्षेत्र के भीतर भी उल्लेखनीय अंतर हैः जनसंख्या घनत्व, आकार, पहुंच, साक्षरता दर, भूमि

स्वामित्व पैटर्न, जाति और वर्ग संरचना, श्रम बाजार संरचना, और सुविधा बंदोबस्ती। तीन बुनियादी मुद्दे अभी भी मौजूद हैं: स्वच्छता, जल निकासी और बिजली वितरण। ग्रामीण इलाकों में, कृषि रोजगार का प्रमुख स्रोत बनी हुई है; फिर भी, बिहार मौसम से संबंधित आपदाओं के लिए कुख्यात है। बार-बार आने वाली बाढ़ और सूखे का लोगों, जानवरों और गाँव की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। बिहार की एक बढ़ती हुई आबादी को तुलनात्मक रूप से स्थिर कृषि में पर्याप्त काम नहीं मिला है। गाँव से पलायन या आवागमन के माध्यम से, कृषि के अलावा नौकरियों की खोज में वृद्धि हुई है। गाँव प्रवास की आवृत्ति में बहुत भिन्न होते हैं। "प्रवासी परिवारों" का प्रतिशत, या वे जहां कम से कम एक व्यक्ति प्रश्नावली से पहले वर्ष के दौरान गांव के बाहर काम करता था, 27% और 89% के बीच भिन्न होता है। बस्तियों की सामान्य स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, दो सूचकांकों-एक विकास सूचकांक और एक दूरस्थता सूचकांक-की गणना की गई है। बेहतर है।सबसे गरीब गाँव मधुबनी, पूर्णिया, अरारिया और गया में थे, जबकि अधिकांश पीट-पीट कर मार दिए गए गाँव रोहतास और गोपालगंज में थे। नालंदा की बस्तियाँ मध्य सीमा का हिस्सा थीं। [3]. कृषि और सामाजिक संरचना: जाति, वर्ग, संपत्ति और संसाधन ग्रामीण गरीबी और ठहराव ऐतिहासिक रूप से बिहार में शोषक कृषि संबंधों के कारण थे। वे भूमि स्वामित्व, जाति और वर्ग से निकटता से संबंधित हैं-ग्रामीण बिहार में असमानता के तीन मुख्य, स्पष्ट पहलू। वर्ग समग्र रूप से सबसे शक्तिशाली घटक है, हालांकि जाति, भूमि और वर्ग सभी का आर्थिक आचरण पर अनूठा प्रभाव पड़ता है। पिछले 30 वर्षों के दौरान वर्ग पैटर्न में काफी बदलाव आया है। 1982 में, संलग्न कृषि श्रम सभी घरों का छठा हिस्सा था; अब, यह अनिवार्य रूप से अस्तित्व में नहीं है। गरीब किसान और अनौपचारिक कृषि मजदूर बढ़ रहे हैं, जबकि जमींदारों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। सामान्य भूमि स्वामित्व स्वरूप विकसित हो रहा है। पिछले तीन दशकों में भूमिहीनता बढ़ी है, हालांकि यह अभी भी मुख्य रूप से गरीब मुसलमानों, ओबीसी I और अनुसूचित जातियों के बीच है।

इस तथ्य के बावजूद कि भूमि का सामान्य वितरण कम असमान हो गया है, आधी से अधिक ग्रामीण आबादी अभी भी भूमिहीन है। बंधुआ श्रम के अंत से पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को लाभ हुआ है, लेकिन केवल एक छोटी संख्या छोटी कृषक बन गई है; मध्यम जातियों ने उच्च जातियों की तुलना में भूमि प्राप्त की है और समग्र रूप से अपनी स्थिति बनाए रखी है; और अगड़ी जातियों ने गैर-कृषि व्यवसायों में विविधता लाई है। कई यादव परिवार अपनी भूमि में वृद्धि करके भूमिहीन और सीमांत किसानों की स्थिति से ऊपर उठ गए हैं। जबकि कुछ ब्राह्मण और कुर्मी घरों का आकार कम हो गया है, अन्य ने ज्यादातर चीजों को वैसे ही रखा है जैसे वे हैं। हालांकि पट्टे पर दी गई भूमि का प्रतिशत पिछले 40 वर्षों में लगभग 28% पर स्थिर रहा है, परिवारों द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि की औसत मात्रा कम परिवारों के पट्टे के रूप में बढ़ी है। जिनके पास भूमि के छोटे टुकड़े हैं, विशेष रूप से बहुत छोटे भूखंड, फिर भी अक्सर अपनी संपत्ति को पट्टे पर देते हैं, जो उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि का एक बड़ा हिस्सा है। जबकि बटाई का मुख्य तरीका बना हुआ है, किरायेदारी तेजी से बाजार संबंधों और अर्ध-सामंती शोषण के बजाय मध्यम जातियों की शक्ति को दर्शाती है। मध्यम जातियाँ, विशेष रूप से यादव, बहुत सारी भूमि पट्टे पर देते हैं, जो कृषि विकास और उत्पादन में उनके महत्व को दर्शाता है, जबकि उच्च जातियाँ बहुत कम पट्टे पर देती हैं। हालाँकि कुल जनसंख्या में भूमि किराए पर लेने वाले परिवारों का प्रतिशत कम हो गया है, लेकिन अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग एक-चौथाई परिवार ऐसा करना जारी

रखते हैं।

ग्रामीण बिहार में कुल मिलाकर घरेलू संपत्ति काफी कम है। कुल संपत्ति का 75-80% भूमि से बना है, शेष भाग का अधिकांश हिस्सा घरों से आता है। जाति और क्षेत्र के आधार पर संपत्ति जोत में अंतर वर्ग, श्रम स्थिति, शिक्षा और परिवार के मुखिया की उम्र और लिंग की तुलना में कम स्पष्ट है। सभी जातियों और सामुदायिक समूहों ने पिछले 40 वर्षों में औसत संपत्ति जोत में वृद्धि देखी है, हालांकि अनुसूचित जातियों, ओबीसी I और यादवों को सबसे अधिक लाभ हुआ है, जबकि यादवों के अलावा उच्च जातियों और मध्यम जातियों को सबसे कम लाभ हुआ है। परिसंपत्ति असमानता का जाति स्वरूप वर्ग स्वरूप की तुलना में अधिक तेजी से विकसित हो रहा है क्योंकि, औसतन, परिसंपत्ति धारण में दीर्घकालिक परिवर्तनों में जातियों के बीच असमानताएं वर्गों के बीच अंतर से अधिक हैं। घरेलू परिसंपत्तियों और भूमि मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि पशुधन और उत्पादक परिसंपत्तियों में बहुत कम वृद्धि हुई है। सभी जनसांख्यिकीय समूहों के पास सेल फोन और साइकिल सहित कुछ वस्तुएँ हैं, जो बदलती जीवन शैली को दर्शाती हैं। मौजूदा घरेलू परिसंपत्तियों का ऋण उपलब्धता के साथ पर्याप्त संबंध है। प्रति परिवार लगभग 9900 रुपये के औसत ऋण के साथ, ऋण प्रवाह बेहद अपर्याप्त है। सामान्य रूप से परिसंपत्तियों की तरह, ऋण-विशेष रूप से संस्थागत ऋण-अमीर परिवारों में बहुत अधिक केंद्रित हैं। [5]. रोजगार, मजदूरी और श्रम बाजार पिछले 30 वर्षों में ग्रामीण बिहार रोजगार बाजार में काफी बदलाव आया है। एक अधिक खुली, बाजार-संचालित प्रणाली ने स्थिर, अर्ध-सामंती प्रणाली की जगह ले ली है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रमिकों को अलग-अलग स्तरों के बंधन के अधीन किया गया था। इस प्रणाली में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम प्रवास ने नई संभावनाएं पैदा की हैं और निर्भरता के स्थानीय संबंधों में कमी आई है। भूमि के बढ़ते दबाव के परिणामस्वरूप अब अधिक परिवार मजदूरी के काम पर निर्भर हैं। स्थानीय रोजगार बाजारों का विकास धीमा रहा है और स्थानीय संभावनाएं बहुत कम बनी हुई हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में और वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान श्रमशक्ति की कमी होती है, जिससे वेतन पर दबाव पड़ता है। नतीजतन, अनुबंध रोजगार जैसी नई संगठनात्मक संरचनाएं अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। जब श्रम बल भागीदारी दर की एक व्यापक परिभाषा लागू की जाती है, तो दरें अक्सर अधिक होती हैं: पुरुषों के लिए 84% और महिलाओं के लिए 38%, और पुरुषों के लिए 91% और महिलाओं के लिए 62%। हालांकि पिछले तीन दशकों में पुरुषों की श्रम बाजार में भागीदारी मजबूत रही है, लेकिन प्रवास के परिणामस्वरूप उनकी नौकरियों की प्रकृति बदल गई है, जिससे आकस्मिक काम के अलावा उद्योग और सेवाओं दोनों में बड़ी मात्रा में नियमित श्रम पैदा होता है। हालांकि श्रम बाजार में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है, लेकिन उनकी रोजगार संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है। कृषि और पशुपालन समुदायों में प्रमुख आर्थिक गतिविधि बनी हुई है। पुरुषों की तुलना में, महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी पर जाति और वर्ग का कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। 1980 और 2010 के बीच, कृषि में व्यवसायों का प्रतिशत 85% से गिरकर 70% हो गया, जो व्यवसाय के महत्व में कमी का संकेत देता है।

इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप कुल नौकरी संरचना बदल गई है, जो स्पष्ट रूप से पिछले दस वर्षों के दौरान तेज हो गई है। 1980-1985 और 1998-2005 के बीच आकस्मिक श्रमिकों का प्रतिशत बढ़ गया, मुख्य रूप से स्व-रोजगार की कीमत पर। आकस्मिक श्रमिकों का प्रतिशत 1998-2005 और 2010-2012 के बीच कार्यबल के आधे से अधिक पर स्थिर रहा, जबकि स्व-नियोजित लोगों के प्रतिशत में गिरावट जारी रही और

नियमित गैर-कृषि नौकरियों, प्रवासन द्वारा संभव बनाया गया, में वृद्धि हुई। रोजगार की संभावनाओं के सृजन में एक कारक शिक्षा है। यह प्राथमिक विद्यालय के बाद से व्यावसायिक विविधीकरण से जुड़ा हुआ है, हालांकि माध्यमिक शिक्षा का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बेहतर वेतन वाली आधुनिक सेवा, पेशेवर और सफेदपोश नौकरियां केवल उच्च शैक्षिक स्तरों पर अधिक प्रचलित हो रही हैं। स्कूल में उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, विशेष रूप से लड़कियों में, बाल श्रम एक मुद्दा बना हुआ है। युवाओं को शुरू में कार्यबल में आने में परेशानी होती है। एक व्यापक व्यावसायिक संरचना केवल 25-40 आयु सीमा में दिखाई देती है। ग्रामीण बिहार में मजदूरी की व्यवस्था जटिल और तेजी से विविध होती जा रही है। पिछले तीन दशकों में वास्तविक दैनिक वेतन में दो से तीन के अनुपात में वृद्धि हुई है। पुरुषों के लिए औसत दैनिक मुआवजा वर्तमान में लगभग 200 रुपये है, जो 2011-12 के मनरेगा श्रमिकों के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कुछ कम है। हालाँकि यह प्रत्येक बस्ती में अलग-अलग है, लेकिन उनमें से कुछ में पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर कम हो गया है। मजदूरी संस्थान, जैसे कि भुगतान के रूप में या फसल के एक हिस्से के रूप में, मजदूरी के स्तर में उतना बदलाव नहीं आया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। हालांकि जिलों के बीच अंतर अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फसल के हिस्से और दैनिक वेतन के बराबरी की दिशा में एक प्रवृत्ति रही है (सबसे बड़ा लाभ दर्ज किया गया है जहां वे पहले सबसे कम थे) [6]. प्रवास प्रक्रिया 40 साल की शोध अवधि के दौरान, ग्रामीण बिहार छोड़ने वाले लोगों की संख्या में महत्वपूर्ण और लगातार वृद्धि हुई है। 1999-2000 और 2010-15 के बीच, सभी श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रमिकों का प्रतिशत 15.9% से बढ़कर 25.6% हो गया। दक्षिण बिहार के अधिक समृद्ध जिलों की तुलना में, उत्तर बिहार के पिछड़े जिलों में प्रवास दर अधिक है। हालाँकि, दोनों क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही, रोजगार की स्थिति और व्यावसायिक विशेषताओं की लंबाई में काफी अंतर था। महानगरीय क्षेत्रों में प्रवास का अधिकांश हिस्सा रोजगार के लिए है। समय के साथ, प्रवास की प्रकृति मौसमी से दीर्घकालिक होने में बदल गई है। 1999-2000 से 2010-2011 तक, प्रवासी धारा में दीर्घकालिक श्रमिकों का प्रतिशत 40.4% से बढ़कर 49.6% हो गया। साथ ही, अस्थायी प्रवास का अनुभव करने वाले परिवारों का प्रतिशत 1985-1987 में 29.4% से बढ़कर 1999-2000 में 24.6% और 2010-2015 में 36.0% हो गया। सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों में मुसलमानों की प्रवासन दर सबसे अधिक है, इसके बाद ओबीसी I, एससी/एसटी, ओबीसी II और उन्नत जातियां आती हैं। वर्ग के संदर्भ में, गैर-कृषि और मकान मालिक परिवारों के पलायन करने की अधिक संभावना है। प्रवास भूमि के स्वामित्व और भूमि की मात्रा से प्रभावित होता है। समृद्ध क्षेत्रों में धनी जमींदार और गरीब जिलों में भूमिहीन दोनों ही अधिक बार पलायन करते हैं। प्रवासी और गैर-प्रवासी घरों के बीच, घर के आकार में उल्लेखनीय अंतर हैं। प्रवासी परिवार प्रत्येक जाति, वर्ग और भूमि श्रेणी में गैर-प्रवासी परिवारों से बड़े हैं। बड़े भूस्वामियों के लिए, जिन्होंने प्रवास का सबसे बड़ा स्तर भी देखा, असमानता विशेष रूप से जाति के आधार पर, उच्च जाति के लिए, वर्ग के आधार पर, जमींदारों के लिए और उनके पास मौजूद संपत्ति के आकार के आधार पर ध्यान देने योग्य है। अधिकांश प्रवासी श्रमिकों-पाँच में से लगभग तीन-के पास बहुत कम या कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है। इस बीच, अनपढ़ श्रमिकों की प्रवास दर सबसे कम है, और शैक्षिक प्राप्ति बढ़ने के साथ यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, July-December 2024, Submitted in July 2024, ISSN -2393-8048

प्रमुख खोजों का अवलोकन

लगभग 97% प्रवासी मजदूर वेतन के लिए काम करते हैं। प्रवासी श्रमिकों का बड़ा हिस्सा आकस्मिक मजदूरी करने वाले श्रमिक हैं, जबकि नियमित मजदूरी करने वाले श्रमिक दूसरे स्थान पर हैं। यात्रा की अवधि का प्रवासी श्रमिकों की श्रम स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता है। जबकि दीर्घकालिक प्रवासी नियमित वेतनभोगी श्रमिक होते हैं, अल्पकालिक प्रवासी मुख्य रूप से आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिक होते हैं। ग्रामीण बिहार के आधे से अधिक प्रवासी श्रमिक तीन प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत हैं: कृषि, निर्माण और उद्योग। प्रवासी मजदूरों के व्यवसाय जिले के अनुसार काफी भिन्न होते हैं। पूर्णिया और मधुबानी के अधिकांश प्रवासी कृषि में काम करते हैं। प्रति परिवार प्रवासी सदस्यों की संख्या, वे किस तरह की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, और उनके प्रवास की अवधि सभी प्रवासियों के घर लौटने की राशि को प्रभावित करते हैं। स्वाभाविक रूप से, जब कोई जाति की सीढ़ी चढ़ता है और गरीब से समृद्ध पड़ोस में जाता है, तो भेजे गए धन की मात्रा बढ़ जाती है। घर के भीतर और बाहर महिलाएं जो काम करती हैं, वह पुरुष प्रवास के परिणामस्वरूप कई तरह से बदल गया है। वे वर्तमान में कृषि प्रबंधन और पशुपालन जैसे कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं। घर के आसपास उन्हें जितना काम करना पड़ता है, वह बढ़ गया है, और वे अब निर्णय लेने, घरेलू वित्त को संभालने और घर पैसे भेजने में अधिक शामिल हो गए हैं।

अपने पुरुषों की अनुपस्थिति में, उन्हें लाभप्रद परिस्थितियों में ऋण प्राप्त करने और ऋण प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से कुछ पारंपरिक समाजों में पुरुषों के प्रवास से महिलाओं की गतिशीलता में काफी वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में अब महिलाएं अधिक गतिशील हो गई हैं। हालाँकि पुरुष प्रवास के परिणामस्वरूप ग्रामीण बिहार में महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव आया है, लेकिन पितृसत्ता और जाति ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो उन्हें मौलिक रूप से परिभाषित और नियंत्रित करती हैं।[4]. अपर्याप्त आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे निजी निवेश की तरह बिहार के आधिकारिक कृषि निवेश में भी तेजी नहीं आई है। बिहार का प्रति हेक्टेयर कृषि पूंजी निवेश राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है और पंजाब के एक चौथाई से भी कम है (गुरुस्वामी और कौल, 2003)। सिंचाई के बुनियादी ढांचे के मामले में, बिहार और उत्तर प्रदेश ने पर्याप्त निवेश नहीं किया है। पंजाब के 95% और गुजरात के 87% के विपरीत, बिहार और उत्तर प्रदेश क्रमशः अपने कृषि क्षेत्र का केवल 55% और 65% सिंचित करते हैं। अन्य राज्यों की तरह, बिहार के किसानों ने अपर्याप्त सतही जल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और बढ़ते जल तनाव के कारण भूजल सिंचाई की ओर रुख किया है। 1981 के दशक में बिहार में भूजल सिंचाई का उपयोग आसमान छू गया। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि अपर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण सिंचाई, खेत की तैयारी और थ्रेशिंग की लागत बढ़ गई (रामागुंडम, 2009; विश्व बैंक, 2005) कीटनाशकों और उर्वरकों की लागत भी काफी बढ़ गई। हालांकि, निवेश लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, कृषि उत्पाद की कीमत अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रही। नतीजतन, लाभप्रदता में कमी आई और उत्पादन-निवेश मूल्य अनुपात में बदलाव आया। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों ने खेती की लाभप्रदता बनाए रखने के लिए डीजल और बिजली पर मूल्य छूट की पेशकश की। हालांकि, बजटीय सीमाओं के कारण, बिहार सरकार किसानों को इस तरह के लाभ प्रदान करने में असमर्थ थी (किशोर, 2004) इसके अलावा,

अपनी छोटी भूमि जोत और सीमित संसाधनों के कारण, बिहार के अधिकांश किसान खाद्यान्न संग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए मूल्य प्रोत्साहन का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।

बिहार का खाद्यान्न उत्पादन पंजाब के आधे से भी कम और राष्ट्रीय औसत (भारत सरकार, 2007) से कम है। कृषि उत्पादकता वृद्धि को बाधित करने के अलावा, कम सार्वजनिक और निजी निवेश, अपर्याप्त संस्थागत और भौतिक बुनियादी ढांचा, असमान भूमि वितरण, और सामंती तत्वों की निरंतर उपस्थिति सहित एक खराब कृषि सामाजिक संरचना ने भी सामाजिक असमानता को मजबूत किया, जो अर्थव्यवस्था और समाज की सामान्य उन्नति के लिए संरचनात्मक बाधाओं को पैदा करता है। [5]. अंतिम विचार बिहार इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे एक निम्न-स्तरीय संतुलन जाल एक ऐसी अर्थव्यवस्था को फँसा सकता है जो प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इस अध्ययन में बिहार के विकास के खराब स्तर के मूल कारणों की जांच की गई। शोध से पता चला कि बिहार का विकास मार्ग और गति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सामाजिक और आर्थिक से लेकर ऐतिहासिक और राजनीतिक तक, परस्पर संबंधित तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रभावित थी। बिहार के निम्न आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को दिया जा सकता है, जिन्होंने स्थायी निपटान के माध्यम से एक मध्यस्थ शोषक वर्ग बनाने के अलावा कई शहरी और ग्रामीण कारीगरों का समर्थन करने वाले देशी ज्ञान-आधारित व्यवसायों को नष्ट कर दिया। भूमिहीन कृषि मजदूरों के निर्माण और कुलीन सामंती वर्ग के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से, इस रणनीति ने कृषि के विस्तार में भी बाधा डाली। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक श्रमिकों को कृषि मजदूरों में परिवर्तित करके, यह कृषि भूमि पर अधिक दबाव डालता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जिस तरह से ज़ार और जमींदार वर्ग ने रूस में औद्योगीकरण का विरोध किया, उसी तरह इसने न केवल कृषि और उद्योग के विस्तार को धीमा कर दिया है, बल्कि एक अनुत्पादक वर्ग भी पैदा किया है जो लगातार आर्थिक और सामाजिक विकास का विरोध कर रहा है (एसेमोग्लू और रॉबिन्सन, 2006) इसके अतिरिक्त, इस दृष्टिकोण ने वर्ग-आधारित शत्रुता की राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देकर आम भलाई के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए आवश्यक विश्वास को नष्ट कर दिया है (बनर्जी और अय्यर, 2005) आजादी के बाद भी, औपनिवेशिक युग के दौरान शुरू हुआ आर्थिक हाशिए पर रहना जारी रहा। भूमि, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पादक संपत्ति है, कई प्रयासों के बावजूद कम संख्या में अनुपस्थित जमींदारों के हाथों में बनी हुई है। ये जमींदार उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि में निवेश करने में विशेष रूप से रुचि नहीं रखते हैं। इसके विपरीत, बटाईदारों के पास भूमि निवेश करने के साधन और प्रेरणा की कमी है। नतीजतन, कृषि उत्पादन खराब बना हुआ है और भूमि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण निवेश अपर्याप्त बने हुए हैं। संघीय सरकार की माल बराबरी की रणनीति, जिसने बिहार के तुलनात्मक लाभ को कम किया और संसाधन आधारित औद्योगीकरण की गति को धीमा कर दिया, ने हाशिए की प्रक्रिया को और मजबूत किया है। इसके परिणामस्वरूप, भले ही बिहार में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही है। इसने, केंद्र के वित्त पोषण की निरंतर कमी के साथ, इन राज्यों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश करना और अधिक कठिन बना दिया है। इसलिए, राज्यों की बड़ी मानव आबादी खराब कौशल, गरीबी, निरक्षरता और भूख के कारण एक बोझ बनी हुई है। ये दोनों संसाधन संपन्न सरकारें मानव पूंजी की कमी, कमजोर संस्थानों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सामाजिक अशांति

और राजनीतिक अस्थिरता के कारण निम्न-स्तरीय संतुलन के जाल में फंस गई हैं। जाति, वर्ग और जातीयता के विभाजन सहित सामाजिक संरचना के कारण विकास प्रक्रिया अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गई है। इनके साथ-साथ केंद्र से संसाधनों की उपलब्धता को निर्धारित करने वाली केंद्र-राज्य शक्ति की अस्थिर गतिशीलता ने बिहार सरकारों के लिए विकास पहलों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनका समर्थन करना कठिन बना दिया है। उन्होंने निवेश, निजी क्षेत्र की भागीदारी, बुनियादी ढांचे के विकास और कानून के शासन के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने के उनके प्रयासों को भी विफल कर दिया है। सत्ता के संतुलन में हाल के बदलावों के बावजूद, राजनीतिक अशांति, भ्रष्टाचार और कमजोर कानून और व्यवस्था ने निवेश, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अनुकूल परिस्थितियों की स्थापना को रोक दिया है। इस प्रकार बिहार आर्थिक विकास के मामले में पीछे रह गया।

संदर्भ

1. एसेमोग्लू, डी., जॉनसन, एस., और रॉबिन्सन, जे. (2001) तुलनात्मक विकास की औपनिवेशिक उत्पत्तिः एक अनुभवजन्य जांच। अमेरिकी आर्थिक समीक्षा, 91 (5) 1369-1401।

2. एसेमोग्लू, डी., और रॉबिन्सन, जे. (2006) राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आर्थिक पिछड़ेपन। अमेरिकी राजनीति विज्ञान समीक्षा, 100 (1) 115-132।

3. एडलमैन, आई। (2001) विकास सिद्धांत में भ्रांतियाँ और नीति के लिए उनके निहितार्थ। में जी. एम. मेयर, और जे. ई. स्टिग्लिट्ज़ (एड) फ्रंटियर्स ऑफ़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (पीपी. 103-147) वाशिंगटन, डी. सी.: विश्व बैंक। अहलूवालिया, एम. (2000) सुधार के बाद की अवधि में राज्यों का आर्थिक प्रदर्शन। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 35 (19) 1637-1648.

4. अहलूवालिया, एम. (2001) भारत में आर्थिक सुधारों के तहत राज्य स्तर का प्रदर्शन (कार्य पत्र सं. 96) स्टैनफोर्ड, सीएः सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी रिफॉर्म, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। औटी, आर. (2007) प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संचय और संसाधन अभिशाप। पारिस्थितिक अर्थशास्त्र, 61,627-634।

5. बागची, ए. (1976) उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में औद्योगीकरणः कुछ सैद्धांतिक निहितार्थ। विकास अध्ययन जर्नल, 12 (2) 135-164। 6. बागची, ए., और कुरियन, जे. (2005) भारत में क्षेत्रीय असमानताएंः सुधार से पहले और बाद के रुझान और नीति के लिए चुनौतियां। जे. मुईज में (एड।) भारत में आर्थिक सुधारों की राजनीति (पीपी। 323-350) नई दिल्लीः ऋषि।

6.Banerjee, A., & Iyer, L. (2005) इतिहास, संस्थान और आर्थिक प्रदर्शनः भारत में औपनिवेशिक भूमि कार्यकाल प्रणालियों की विरासत। अमेरिकी आर्थिक समीक्षा, 95 (4) 1190-1213।

7. बीयर, ए., एंड क्लोवर, टी. (2014) शहरों और क्षेत्रों में नेतृत्व जुटाना। क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय विज्ञान, 1 (1) 5-20।

8. बेलोट्टी, एल. (2006) आर्थिक संरचना और आर्थिक विकास। अमेरिकन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, 20 (1) 73-80।

9. बोसेरुप, ई. (1965) कृषि विकास की स्थितियाँः जनसंख्या के दबाव में कृषि परिवर्तन का अर्थशास्त्र। लंदनः जॉर्ज एलन और अनविन। ब्रॉक, डब्ल्यू. ए., और डर्लौफ, एस. एन. (2001) विकास पर एक दशक के अनुभवजन्य शोध से हमने क्या सीखा है? विकास अनुभव और वास्तविकता। विश्व बैंक आर्थिक

International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, July-December 2024, Submitted in July 2024, ISSN -2393-8048
समीक्षा, 15 (2) 229-272.
10. ब्रंसच्वीलर, सी. (2008) आशीषों को शाप दे रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, संस्थान और आर्थिक विकास। विश्व विकास, 36 (3) 399-419।
11. बंस, एम. (2004) यह कैसे काम करता है? व्याख्यात्मक तंत्र की खोज। सामाजिक विज्ञान का दर्शन, 34 (2) 182-210।
12. कैली, एम., और सेन, के. (2011) क्या प्रभावी राज्य-व्यापार संबंध आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं? भारतीय राज्यों से साक्ष्य। विश्व विकास, 39 (9) 1542-1557।
13. चांग, H.-J. (2001) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकासशील देशों में संस्थागत विकासः पहले के समय में विकसित देशों से सबक। कैम्ब्रिजः कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। चेनरी, एच. (1979) संरचनात्मक परिवर्तन और विकास नीति। न्यूयॉर्क, एनवाईः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। डिंग, एन., एंड फील्ड, बी. सी. (2005) प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और आर्थिक विकास। भूमि अर्थशास्त्र, 81 (4) 496-502।
14. डॉलर, डी. (1992) बाहरी उन्मुख विकासशील अर्थशास्त्र वास्तव में अधिक तेजी से बढ़ता हैः 95 एलडीसी, 1976-85 से साक्ष्य। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन, 40 (3) 523-544।
15. डोपेलहोफर, जी., मिलर, आर., और साला-ए-मार्टिन, एक्स. (2000) दीर्घकालिक विकास के निर्धारकः शास्त्रीय अनुमानों का एक बायेसियन औसत (बीएसीई) दृष्टिकोण (वर्किंग पेपर नं। 7750) कैम्ब्रिज, एमएः राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो (एनबीईआर)